

की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली अध्यापक परिषद् ने यह मांग की है कि आपातकाल के दौरान अध्यापकों के सेवा रिकार्ड में लिखे गए प्रतिकूल टिप्पण निकाल दिये जायें और कतिपय अध्यापकों को दी गई अनुचित पदोन्नति के मामलों का पुनरीक्षण किया जाये ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चुन्दर) : जी, हां। ये मामले विचाराधीन हैं।

आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विद्यार्थियों का सहयोग

61. श्री कल्याण जैन क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त करने के लिये सरकार के सामने कौन सी योजना विचाराधीन है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चुन्दर) : राष्ट्रीय सेवा योजना जिसे 1969-70 से चालू किया हुआ है, विश्वविद्यालय और कालेज के छात्रों को सामाजिक सेवा और विकासात्मक कार्यक्रमों में लगाने की व्यवस्था पहले से ही करती है। 1976-77 से राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रमों को ग्रामीण पुनर्गठन के लिये कार्यक्रमों के आसपास केन्द्रित किया गया है। इस योजना को धीरे धीरे व्यापक रूप दिया जा रहा है।

विश्वविद्यालयों और कालेजों में खोले गये योजना मंच छात्र समुदाय में देश के योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता की ओर जागरूकता पैदा करते हैं और योजना बनाने के आरंभिक स्तर से ही उनको राष्ट्रीय विकास के काम में लगते हैं।

झालावाड़ (राजस्थान) में मध्यम सिंचाई योजनाएं

62. श्री चतुर्भुज : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झालावाड़ जिला (राजस्थान) में, जो कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, निर्माणाधीन मध्यम सिंचाई योजनाएं इस बीच पूरी हो गई हैं और उन पर अब तक कितना धन खर्च हो चुका है और उन पर कुल कितना धन खर्च होगा और उन से कितना लाभ प्राप्त होगा ; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस जिले में कोई नई बृहत् अथवा प्रथम सिंचाई योजना आरम्भ की है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बाबल, (क) 7,000 हैक्टेयर क्षेत्र के सिंचाई के लिए 5.16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली भीमसागर स्कीम और प्रति वर्ष 8,000 हैक्टेयर भूमि की सिंचित करने के लिए 2.99 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली हरिश्चन्द्र सागर स्कीम से राजस्थान के झालावाड़ जिले को लाभ पहुंचेगा। मार्च, 1977 तक इन स्कीमों पर क्रमशः 62 लाख रुपये और 64 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

(ख) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि उस ने झालावाड़ जिले में निम्नलिखित तीन नई मध्यम परियोजनाओं के बारे में अन्वेषण-कार्य हाथ में लिए हैं और अन्वेषण कार्य जारी है :—

1. मनोहर थाना परियोजना।
2. छपी परियोजना।
3. गंगारिन परियोजना।